दमा के मरीज़ों को प्रदूषण का हर्ज़ाना मिला

टोक्यो के दमा मरीज़ों ने एक महत्वपूर्ण लड़ाई जीती है। उन्हें कार निर्माता कंपनियां और सरकार न सिर्फ मुआवज़ा देंगी बल्कि उनकी सेहत के लिए एक योजना भी चलाएंगी।

यह मुकदमा टोक्यो के सैकड़ों बाशिंदों ने 1996 में दायर किया था। इन लोगों का कहना था कि शहर में ईंधन व कार इंजिनों की घटिया गुणवत्ता के चलते फैले प्रदूषण के कारण ये दमा के शिकार हुए हैं। 2002 में टोक्यो की ज़िला अदालत ने फैसला सुनाया कि कुछ फरियादियों के दमा के लिए सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है मगर कार निर्माता निर्दोष हैं। इस फैसले के विरुद्ध अपील की सुनवाई के बाद टोक्यो के हाई कोर्ट ने सिफारिश की थी कि सारे पक्ष अदालत के बाहर समझौता कर लें।

अदालत के बाहर हुए समझौते के मुताबिक अब तीन कार निर्माता - टोयोटा, होण्डा और निस्सान - फरियादियों को 1.2 अरब येन देंगे और 3.3 अरब येन एक पांच वर्षीय स्वास्थ्य योजना के लिए भी देंगे। इसके अलावा जापान की केंद्र सरकार और टोक्यो की महानगर सरकार भी मरीज़ों के स्वास्थ्य के लिए 6-6 अरब येन उपलब्ध कराएंगी।

वैसे टोक्यो में ईंधन के प्रकार व इंजिन की गुणवत्ता को लेकर कठोर मापदंड 2003 में लागू होने के बाद स्थिति में कुछ सुधार आया है।

इस तरह के मुकदमे अभी बहुत आम नहीं हैं । मगर इसी तरह 2002 में अमेरिका के एक रेल कर्मचारी ने सरकार पर मुकदमा करके मुआवज़े की मांग की थी। कर्मचारी का दावा था कि उसे यह रोग काम के दौरान प्रदूषण से संपर्क के कारण हुआ है। ज्यूरी ने उसे 6.25 लाख डॉलर का मुआवज़ा दिलवाया था।

यह बात जानी-मानी है कि डीज़ल के जलने से निकले कण और सांस सम्बंधी समस्याओं के बीच सीधा सम्बंध है। जैसे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 2002 में किए गए एक अध्ययन से पता चला था कि हवा में तैरते धुएं व अन्य कणों के कारण लगभग 10 लाख दमा के दौरे पड़े। इसके अलावा इस प्रदूषण के कारण हज़ारों लोग असमय मृत्यु के शिकार भी हुए। और यह समस्या सिर्फ जकार्ता की नहीं है। भारत के महानगर भी इससे अछूते नहीं हैं।

इस संदर्भ में चीन की राजधानी बीजिंग में एक प्रयोग होने वाला है। वहां चार दिनों के लिए सारी (13 लाख) कारों को चलने नहीं दिया जाएगा और देखा जाएगा कि कारों के संचालन से प्रदूषण में कितना इज़ाफा होता है। वैसे फिलहाल वहां यह चिंता व्याप्त है कि ओलंपिक आने वाले हैं और प्रदूषित वातावरण का एथलीट्स के प्रदर्शन पर खराब असर पड़ने की आशंका है। देखने वाली बात यह है कि देश के नागरिक चाहे एथलीट्स न हों, उनके सामान्य कामकाज पर भी तो असर पड़ता ही होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***